

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 23-06-2025

विषय सूची

- » मसौदा पंजीकरण विधेयक 2025
- » कीट-आधारित पशुधन आहार के साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से मुकाबला
- » विदेशी विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा को कैसे प्रभावित करेंगे?
- » धीमी होती अर्थव्यवस्था में विस्तारवादी नीतियां
- » क्वांटम संचार

संक्षिप्त समाचार

- » डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
- » उम्मीद पोर्टल
- » ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमला
- » ईरान ने होर्मुज जलडमरुमध्य को अवरुद्ध करने का कदम उठाया
- » सरिस्का बाघ अभ्यारण्य
- » GBU-57 विशाल आयुध भेदक/MOP
- » INS नीलगिरि: प्रथम प्रोजेक्ट 17A स्टील्यू फ्रिगेट
- » INS तमाल

मसौदा पंजीकरण विधेयक 2025

समाचार में

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने नए मसौदा पंजीकरण विधेयक 2025 पर सुझाव आमंत्रित किए हैं।

नया मसौदा पंजीकरण विधेयक 2025

परिचय:

- यह भूमि दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए एक आधुनिक ढांचा स्थापित करने और अधिक नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
 - यह 117 वर्षीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 का स्थान लेगा।
- यह संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण को डिजिटाइज करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखेगा।
- मुख्य विशेषताएँ:** यह भूमि दस्तावेज पंजीकरण के लिए एक आधुनिक, नागरिक-मैत्रीपूर्ण ढांचा प्रस्तुत करता है, जो आधार या वैकल्पिक पहचान सत्यापन के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं की अनुमति देता है।
 - यह पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की सूची का विस्तार करता है, जिसमें विक्रय अनुबंध और कंपनियों के विलय शामिल हैं, साथ ही वैकल्पिक पंजीकरण को भी सरल बनाया गया है, हालांकि इस बारे में विवरण अस्पष्ट हैं।
 - इंस्पेक्टर जनरल की सहायता के लिए अतिरिक्त और सहायक पंजीकरण महानिरीक्षक जैसे नए पद बनाए गए हैं।
 - इंस्पेक्टर जनरल झूठे या अवैध आधार पर किए गए पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, जिसके विरुद्ध 30 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है।
 - विधेयक में कारावास की अधिकतम सजा को सात वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है, साथ ही जुर्माने का प्रावधान है।

मुद्दे और चुनौतियाँ

- इस विधेयक को लेकर चिंताएँ हैं कि डिजिटल रिकॉर्ड और ई-हस्ताक्षर डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा की आवश्यकता होगी।
- इसके अतिरिक्त, पंजीकरण कार्यों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) को सौंपना—जो स्टांप ड्रूटी मूल्यांकन और शीर्षक हस्तांतरण जैसे संवेदनशील कानूनी कार्यों को संभालते हैं—प्रक्रियात्मक खामियों को उत्पन्न कर सकता है।

अन्य संबंधित पहलें:

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):** इसे 2016 में 100% केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में पुनः प्रारंभ किया गया था।
 - इसका उद्देश्य एक आधुनिक, पारदर्शी और एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रणाली बनाना है।
 - इसके लक्ष्य हैं: रियल-टाइम भूमि जानकारी में सुधार, भूमि उपयोग का अनुकूलन, भूमि मालिकों और नीति निर्माताओं को सहायता देना, विवादों और धोखाधड़ी को कम करना, भौतिक कार्यालय यात्राओं की आवश्यकता को कम करना, और विभिन्न एजेंसियों के बीच डेटा साझा करने को सक्षम करना।
- स्वामित्व योजना (SVAMITVA):** यह 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है, जिसके अंतर्गत गांवों के जनसंख्या क्षेत्र में संपत्ति मालिकों को “अधिकारों का रिकॉर्ड” प्रदान किया जाता है।
 - ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग करके भूमि सीमांकन किया जाता है, जिससे संपत्ति का मुद्रीकरण, बैंक ऋण तक पहुंच, विवादों में कमी और गांव-स्तरीय योजना में सहायता मिलती है—यह ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है।
- नक्शा कार्यक्रम (NAKSHA):** यह भूमि संसाधन विभाग की एक तकनीकी पहल है, जिसे सर्वे ऑफ

इंडिया और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर क्रियान्वित किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाना है।

- ▲ यह भारत की तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की पृष्ठभूमि में सत्यापन योग्य और सुलभ भूमि रिकॉर्ड की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करता है।

Source :IE

कीट-आधारित पशुधन आहार के साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से मुकाबला

संदर्भ

- पशुपालन में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, भारत एएमआर-प्रतिरोधी खाद्य प्रणाली बनाने के लिए आईसीएआर (ICAR) के नेतृत्व में साझेदारी के माध्यम से कीट-आधारित पशु चारे में नवाचार को आगे बढ़ा रहा है।

क्या है रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)?

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंकूंद और परजीवी समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, जिससे संक्रमणों का उपचार करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी व मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
- प्रत्येक वर्ष लगभग 7 लाख लोगों की एएमआर के कारण मृत्यु हो जाती है।
 - ▲ यह संख्या 2050 तक 1 करोड़ तक पहुँच सकती है और वैश्विक वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.8% प्रभावित कर सकती है।

पारंपरिक पशु आहार एएमआर में कैसे योगदान देता है?

- विश्व भर में कुल एंटीबायोटिक दवाओं का 50% से अधिक उपयोग पशु कृषि में होता है।
- इन्हें केवल बीमारियों के उपचार के लिए नहीं, बल्कि पशुओं की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

- हालांकि, जानवरों में आंतों के बैक्टीरिया को लगातार एंटीबायोटिक के संपर्क में रखने से एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन (ARGs) का विकास होता है, जो भोजन की श्रृंखला, जल, मिट्टी और सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों तक पहुँच सकते हैं।

कीट-आधारित चारे का महत्व

- एएमआर में कमी लाना:** कीटों में डिफेन्सिन्स और सेक्रोपिन्स जैसे रोगाणुरोधी पेप्टाइड्स (AMPs) होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से जानवरों की प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं और रोग की घटनाओं को कम करते हैं, जिससे एंटीबायोटिक की आवश्यकता घटती है।
- पोषण में श्रेष्ठता:** कीटों में सुपाच्य प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड, वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं।
 - ▲ वे कई मछली व मुर्गी प्रजातियों के प्राकृतिक आहार का भाग भी होते हैं।
- आर्थिक व्यवहार्यता:** शोध दर्शाते हैं कि कीट-आधारित चारे का लाभ-लागत अनुपात पारंपरिक मछली भोजन या सोयाबीन भोजन की तुलना में बेहतर होता है।
 - ▲ स्थानीय स्तर पर इसका उत्पादन प्रोटीन युक्त चारे के महंगे आयात पर निर्भरता को कम करता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विरुद्ध प्रयास

- वैश्विक प्रयास:**
 - ग्लोबल एक्शन प्लान (GAP) on AMR:** 2015 में देशों ने “बन हेल्थ” दृष्टिकोण पर आधारित इस साझा योजना को स्वीकार किया।
 - विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता समाह (WAAW):** यह एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य विश्व भर में AMR के बारे में जागरूकता फैलाना है।
 - वैश्विक एएमआर और उपयोग निगरानी प्रणाली (GLASS):** WHO ने 2015 में इसे शुरू किया ताकि ज्ञान की कमी दूर की जा सके और रणनीतियों का निर्माण किया जा सके।

- ▲ **ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप (GARDP):** यह WHO और ड्रग्स फॉर नेलेक्टेड डिजीजेस इनिशिएटिव (DNDi) की संयुक्त पहल है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहित करती है।
- **भारतीय पहलें:**
 - ▲ **एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR):** इसमें “वन हेल्थ” पद्धति पर ध्यान केंद्रित किया गया है और कई मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से यह शुरू की गई थी।
 - ▲ **एएमआर निगरानी नेटवर्क:** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने एएमआरएसएन (AMRSN) की स्थापना की ताकि साक्ष्य उत्पन्न किया जा सके और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के रुझान व पैटर्न को दर्ज किया जा सके।
 - ▲ **रेड लाइन अभियान:** इस अभियान के अंतर्गत डॉक्टर के पर्चे से मिलने वाली एंटीबायोटिक दवाओं पर लाल रेखा चिन्हित करने की मांग की जाती है ताकि काउंटर से दवाओं की बिक्री को हतोत्साहित किया जा सके।
 - ▲ **राष्ट्रीय एंटीबायोटिक खपत नेटवर्क (NAC-NET):** यह नेटवर्क संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों से एंटीबायोटिक खपत से जुड़े डेटा को एकत्र करता है और उसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को भेजता है।
 - ▲ **ऑपरेशन अमृत:** केरल ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा शुरू की गई यह पहल राज्य में एंटीबायोटिक के अति-उपयोग को रोकने के लिए है।

निष्कर्ष

- एएमआर संकट अब केवल भविष्य की चिंता नहीं रह गया है—यह वर्तमान की गंभीर चुनौती है, जो आधुनिक चिकित्सा, कृषि और वैश्विक विकास की नींव को चुनौती दे रहा है।
- कीट-आधारित पशु चारे की ओर परिवर्तन न केवल एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने का

एक क्रांतिकारी अवसर है, बल्कि यह खाद्य प्रणालियों के पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम कर सकता है।

Source: TH

विदेशी विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा को कैसे प्रभावित करेंगे?

संदर्भ

- यूजीसी (भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 द्वारा सक्षम कई विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश ने भारतीय उच्च शिक्षा में एक प्रमुख विकास का संकेत दिया है।

पृष्ठभूमि

- प्रमुख विदेशी संस्थान, मुख्य रूप से GIFT सिटी और नवी मुंबई में शाखा परिसरों की स्थापना कर रहे हैं।
- सिंगापुर के येल-NUS और NYU अबू धाबी उल्लेखनीय सफलताएं हैं—स्थानीय साझेदारियों, उदार राज्य समर्थन और शैक्षणिक स्वायत्ता के कारण।
- यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की दृष्टि के अनुरूप है, जो शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करता है।

विदेशी विश्वविद्यालय भारत में क्यों प्रवेश कर रहे हैं?

पश्चिम में प्रेरक कारक:

- ▲ **जनसांख्यिकीय बदलाव:** यू.के., कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई ग्लोबल नॉर्थ देश घटती जन्म दर के कारण घरेलू नामांकन में गिरावट का सामना कर रहे हैं।
- ▲ **वित्तीय दबाव:** कई पश्चिमी देशों में उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक फंडिंग में गिरावट आई है।
 - परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालयों ने फंडिंग अंतर को भरने के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों की ओर रुख किया है, जो काफी अधिक ट्र्यूशन शुल्क देते हैं।
- ▲ **हालिया वीजा और नीति परिवर्तन:** यू.के., ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा

- पर सीमा या कड़े नियंत्रण लगाए हैं, जिससे उनके विश्वविद्यालयों की आय प्रभावित हुई है।
- ▲ **बजट कटौती:** घटते नामांकन और आय के कारण कई विश्वविद्यालयों ने छंटनी शुरू कर दी है, जिससे भारत जैसे विदेशी बाजारों की खोज अधिक आवश्यक हो गई है।
 - **भारत में आकर्षण के कारक:**
 - ▲ **बड़ी युवा जनसंख्या:** भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है। 4 करोड़ से अधिक छात्र उच्च शिक्षा में हैं और सकल नामांकन अनुपात (GER) लगभग 30% है—गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ रही है।
 - ▲ **बढ़ता हुआ मध्यवर्ग:** बढ़ती आय और आकांक्षाएं प्रीमियम शिक्षा को भारतीय परिवारों के लिए अधिक सुलभ बना रही हैं।
 - ▲ **नियामक सुधार:** एफएचईआई विनियम 2023 शीर्ष रैंकिंग वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को संचालनात्मक स्वायत्ता के साथ भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देते हैं।
 - ▲ **एनईपी 2020 के लक्ष्य:** यह नीति वैश्विक साझेदारियों, ज्ञान विनियम और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है—जिससे एक अनुकूल नीति पारिस्थितिकी तंत्र बनता है।

विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों के लाभ

- **बेहतर शैक्षणिक मानक:** शीर्ष विदेशी संस्थानों से वैश्विक शिक्षण पद्धतियाँ, संकाय प्रशिक्षण, अंतर्विषयक पाठ्यक्रम और अनुसंधान उन्मुखता लाने की अपेक्षा है।
- **अंतरराष्ट्रीय डिग्री:** जो छात्र विदेश जाने का व्यय नहीं वहन कर सकते, वे भारत में कम लागत पर अंतरराष्ट्रीय डिग्री प्राप्त कर सकेंगे।
- **विदेशी मुद्रा पर भार कम होना:** भारत हर साल लगभग \$60 बिलियन शिक्षा के लिए विदेश भेजता है—यह कदम उस पर रोक लगाएगा।
- **ब्रेन ड्रेन पर नियंत्रण:** भारत में ही उच्च गुणवत्ता के अवसर मिलने से कुछ छात्र यहीं रुकना पसंद कर सकते

हैं, जिससे प्रतिभा के पलायन में कमी आएगी।

- **सहयोग के अवसर:** ये परिसर विशेषकर STEM, AI, जलवायु विज्ञान, फिनटेक और लिबरल आर्ट्स में उद्योग-अकादमिक साझेदारी के केंद्र बन सकते हैं।
- **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:** GIFT सिटी और नवी मुंबई जैसे स्थानों को शैक्षिक-आर्थिक केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है, जहाँ छात्र इंटर्नशिप, स्टार्टअप इनक्यूबेटर और वैश्विक कॉर्पोरेट नेटवर्क तक पहुँच बना सकते हैं।

चुनौतियाँ

- **सीमित प्रारंभिक प्रभाव:** लघु और मध्यम अवधि में पैमाना छोटा होगा—प्रत्येक परिसर में शुरुआती नामांकन कुछ हजार छात्रों तक सीमित रह सकता है।
- **लागत संबंधी चिंताएँ:** यदि विदेशी परिसर अपने मूल देश की फीस संरचना को अपनाते हैं, तो औसत भारतीय छात्रों के लिए पहुंच कठिन हो सकती है।
- **संचालन संबंधी अड़चनें:** यूजीसी के उदार मानदंडों के बावजूद भूमि अधिग्रहण, मान्यता मान्यता और संकाय भर्ती मानदंडों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
- **विफलता के उदाहरण:** मलेशिया, यूएई और चीन में कई विदेशी परिसर या तो बंद हो गए हैं या कम नामांकन या सांस्कृतिक असामंजस्य के कारण अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे।

आगे की राह

- **स्तरीय शुल्क संरचना:** समावेशन सुनिश्चित करने के लिए परिसरों को छात्रवृत्ति, आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता और भिन्न शुल्क दरों देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **स्पष्ट गुणवत्ता आश्वासन तंत्र:** यूजीसी और एनएसी को मजबूत निगरानी तंत्र बनाना चाहिए ताकि विदेशी परिसर वैश्विक मानकों को बनाए रखें और भारतीय मूल्यों के अनुरूप रहें।
- **मजबूत स्थानीय साझेदारियाँ:** विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों, उद्योग संगठनों और

- अनुसंधान संस्थानों से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि सामग्री का स्थानीयकरण और पहुंच बढ़ सके।
- नियमित प्रभाव आकलन:** एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी व्यवस्था को छात्र संतोष, अनुसंधान आउटपुट और रोजगारप्रक्रिया के परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, बशर्ते इसे यथार्थवादी ढंग से अपनाया जाए।
- इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितने सुलभ, समावेशी और भारतीय शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए हैं।
- यदि इसे समझदारी से अपनाया गया, तो यह भारत की वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को साकार करने में सहायक हो सकता है, जैसा कि एनईपी 2020 में कल्पना की गई है।

Source: TH

धीमी होती अर्थव्यवस्था में विस्तारवादी नीतियाँ

संदर्भ

- भारत वर्तमान में एक दुर्लभ चरण का साक्षी बन रहा है जहाँ राजकोषीय और मौद्रिक दोनों नीतियाँ विस्तारवादी हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य धीमी होती अर्थव्यवस्था में समग्र माँग को पुनर्जीवित करना है, लेकिन इससे महँगाई, नीति असंतुलन और राजकोषीय दबाव का जोखिम भी उत्पन्न होता है।

हाल ही में अपनाई गई प्रमुख नीतियाँ

- वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में ₹11.21 लाख करोड़ का प्रावधान अवसंरचना, कृषि, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों (MSMEs) और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए किया गया (पूँजीगत व्यय पर विशेष बल)।

- घोषित आयकर कटौतियों का उद्देश्य मंदी के दौरान खपत को बढ़ावा देना था।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंद होती वृद्धि के बीच उधारी और निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु रेपो दर घटाकर 5.5% कर दी।
- RBI के दोहरे लक्ष्य — मूल्य स्थिरता और वृद्धि — ने निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ उत्पन्न कीं:
 - उधारी को प्रोत्साहन देने हेतु दरों में कटौती।
 - मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण, जिससे खुदरा मुद्रास्फीति 2024-25 में घटकर 4.6% पर आ गई।
 - वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी (NBFCs) को तरलता समर्थन।

मुद्दे और चुनौतियाँ

- नीति समन्वय की कमी: यदि दोनों नीतियाँ बिना समन्वय के एक साथ काम करेंगी तो इससे अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उतार-चढ़ाव आ सकता है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
 - इन नीतियों के बावजूद, वृद्धि धीमी है, ऋण प्रवाह कमज़ोर है और बेरोजगारी बढ़ रही है।
- माँग की मंद प्रतिक्रिया: कर कटौती के बावजूद लोग व्यय नहीं कर रहे हैं।
 - यह युक्तियुक्त अपेक्षा सिद्धांत (Rational Expectations Theory) को चुनौती देता है।
- विस्तारित राजकोषीय घाटे का जोखिम: यदि वृद्धि नहीं होती, तो कर राजस्व घटेगा, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा।
 - इस अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार को कल्याणकारी व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे कमज़ोर वर्गों को क्षति होगी।
- बढ़ती असमानता और कमज़ोर मज़दूरी: कॉर्पोरेट लाभ बढ़ रहा है लेकिन वास्तविक वेतन स्थिर हैं।
 - विस्तारवादी नीतियाँ पूँजी को मज़दूरों की तुलना में अधिक लाभ पहुंचा सकती हैं।

विस्तारवादी नीतियों के अंतीत में अपनाए गए उदाहरण

- न्यू डील (1930s): अमेरिका द्वारा महामंदी की प्रतिक्रिया स्वरूप।
- 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट के बाद: केंद्रीय बैंकों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती और मात्रा आधारित सहजता (Quantitative Easing) — सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा तरलता बढ़ाई गई।
 - भारत में RBI ने 2008 में रेपो दर को 9% से घटाकर अप्रैल 2009 में 4.75% किया।
- जापान की 'अबे-नोमिक्स' (2012–2020): तीन स्तंभों वाली रणनीति —
 - बैंक ऑफ जापान द्वारा मौद्रिक सहजता;
 - सरकारी व्यय के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहन;
 - स्थिर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संरचनात्मक सुधार।
- कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया (2020–2021):
 - विशाल राजकोषीय प्रोत्साहन — नकद हस्तांतरण, बेरोज़गारी भत्ता और व्यापार क्रण;
 - केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती और परिसंपत्ति खरीद में विस्तार। भारत ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत ₹20 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च किया। अन्य उपाय:
 - रेपो दर को ऐतिहासिक निम्नतर स्तर 4% तक लाना।
 - क्रण स्थगन और एनबीएफसी व हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए तरलता समर्थन।

भारत में विस्तारवादी नीतियों के लाभ

- समग्र माँग को बढ़ावा: कर कटौती एवं सार्वजनिक व्यय जैसे विस्तारवादी राजकोषीय उपाय लोगों की आय और खपत को बढ़ाते हैं।
 - इसी तरह, कम ब्याज दरें क्रण और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में माँग पुनर्जीवित होती है।

- रोजगारों का सृजन: सरकार द्वारा वित्तपोषित अवसंरचना परियोजनाएँ और MSME समर्थन योजनाएँ विशेष रूप से ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार सृजित कर सकती हैं।
- निजी निवेश को प्रोत्साहन: उधारी की कम लागत और बेहतर उपभोक्ता भावना कंपनियों को क्षमता विस्तार, नवाचार एवं भर्ती के लिए प्रेरित कर सकती है।
- वित्तीय बाजारों को स्थिरता: RBI द्वारा तरलता इंजेक्शन और NBFCs व बैंकों के लिए क्रण गारंटी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायक हैं।
- अल्पकालिक आर्थिक राहत: कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों में नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा उपायों ने कमज़ोर वर्गों को तत्काल राहत दी।

आगे की राह

- नीति समन्वय तंत्र को मजबूत करें: RBI और वित्त मंत्रालय के बीच संस्थागत संवाद स्थापित करें।
- लक्षित हस्तांतरण को प्राथमिकता दें: DBT और मजदूरी समर्थन योजनाओं को बढ़ाएँ ताकि निचले स्तर से माँग को प्रोत्साहन मिले।
- कर संरचना का समग्र पुनरीक्षण करें: आयकर राहत को अप्रत्यक्ष कर (GST) सरलीकरण के साथ जोड़ा जाए।
- मुद्रास्फीति की सक्रिय निगरानी करें: यदि माँग आधारित मुद्रास्फीति बढ़े तो समय रहते मौद्रिक नीति को सख्त किया जाए।

निष्कर्ष

- विस्तारवादी नीतियों ने विशेषकर संकट के समय में भारत की आर्थिक प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, इनकी सफलता समय-निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण और समन्वय पर निर्भर करती है।
- नीतिनिर्माताओं को अल्पकालिक प्रोत्साहन और दीर्घकालिक राजकोषीय अनुशासन एवं संरचनात्मक सुधारों के बीच संतुलन साधने की आवश्यकता है ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

राजकोषीय नीति

- यह सरकार द्वारा कराधान और सार्वजनिक व्यय के उपयोग को संदर्भित करती है ताकि अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जा सके।
- विस्तारवादी राजकोषीय नीति:** माँग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी व्यय बढ़ाना या करों में कटौती करना।
- संकुचनकारी राजकोषीय नीति:** अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाली अर्थव्यवस्था को संतुलित करने या राजकोषीय घाटा कम करने के लिए व्यय में कटौती या कर वृद्धि।
 - सरकार दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने हेतु FRBM अधिनियम जैसी राजकोषीय जिम्मेदारी रूपरेखाओं का उपयोग करती है।

मौद्रिक नीति

- यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रबंधित होती है और इसमें ब्याज दरों व मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता एवं विकास में सहयोग देना शामिल होता है।
- विस्तारवादी मौद्रिक नीति:** ब्याज दरों को घटाना या खुले बाज़ार संचालन द्वारा तरलता का संचार करना।
- संकुचनकारी मौद्रिक नीति:** मुद्रास्फीति पर नियंत्रणपाने हेतु ब्याज दरों में वृद्धि या मुद्रा आपूर्ति में कमी करना।

Source: TH

क्वांटम संचार

संदर्भ

- भारत ने IIT दिल्ली स्थित DRDO-उद्योग-अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (DIA-CoE) द्वारा मुक्त अंतरिक्ष के माध्यम से क्वांटम उलझाव (Quantum Entanglement) का उपयोग करते हुए क्वांटम सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह भारत के क्वांटम तकनीक रोडमैप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है।

प्रमुख विशेषताएँ

- प्रयुक्त तकनीक:** क्वांटम उलझाव-आधारित मुक्त-अंतरिक्ष क्वांटम कुंजी वितरण (QKD)।
- सुरक्षित कुंजी दर:** ~240 बिट प्रति सेकंड।
- क्वांटम बिट त्रुटि दर (QBER):** < 7%।
- दूरी:** IIT दिल्ली परिसर में 1 किलोमीटर से अधिक की मुक्त-अंतरिक्ष ऑप्टिकल लिंक।

क्वांटम संचार

- क्वांटम संचार क्वांटम भौतिकी, विशेष रूप से क्वांटम उलझाव,** का उपयोग करता है ताकि सूचनाओं को भेजने के लिए अत्यधिक सुरक्षित चैनल बनाए जा सकें।
- क्वांटम उलझाव:** जब दो फोटॉन उलझित होते हैं, तो उनमें से एक को मापने से दूसरे की स्थिति तुरंत ज्ञात हो जाती है — चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों।
- मुख्य उद्देश्य:** संचार को पूर्णतः लीक-प्रूफ बनाना।
 - किसी भी जासूसी प्रयास से उलझी हुई स्थिति में गड़बड़ी होगी, जिससे हस्तक्षेप का पता चल जाएगा।

क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) क्या है?

- QKD क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके एन्क्रिप्शन कुंजियों का सुरक्षित आदान-प्रदान सक्षम करता है। यह फोटॉनों (प्रकाश कणों) का सूचना वाहक के रूप में उपयोग करता है।
- क्वांटम उलझाव-आधारित QKD अत्यधिक सुरक्षित है — किसी भी हैकिंग प्रयास से प्रणाली में कमियाँ होती हैं और वह तुरंत पता चल जाती है।
- क्वांटम उलझाव-आधारित QKD के लाभ:**
 - दोषपूर्ण या समझौता किए गए उपकरणों के बावजूद सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
 - क्वांटम स्थिति में कमियों के माध्यम से घुसपैठ का पता चलता है।
 - पारंपरिक “तैयार-और-माप” QKD तरीकों की तुलना में अधिक मजबूत।
- अनुप्रयोग:**
 - रक्षा संचार।

- ▲ सुरक्षित बैंकिंग और दूरसंचार नेटवर्क।
- ▲ रणनीतिक क्षेत्र में डेटा की सुरक्षा।
- ▲ **लागत-कुशल:** कठिन क्षेत्रों में महंगे फाइबर बिछाने की आवश्यकता से बचते हुए मुक्त-अंतरिक्ष QKD स्स्ता विकल्प है।

मुक्त-अंतरिक्ष संचार क्यों?

- मुक्त-अंतरिक्ष या उपग्रह-आधारित QKD बिना केबल बिछाए लंबी दूरी पर जुड़ सकता है।
- केबल (ऑप्टिकल फाइबर) लंबी दूरी पर महंगे और अव्यवहारिक हो जाते हैं।
- वैश्विक तुलना
 - ▲ चीन 2021 से 4,600 किलोमीटर लंबा क्वांटम नेटवर्क संचालित कर रहा है।
 - ▲ चीन ने लगभग एक दशक पहले ही उपग्रह-आधारित क्वांटम संचार का प्रदर्शन कर लिया था, क्योंकि उसने 2000 के दशक की शुरुआत से क्वांटम गतिविधियों में बढ़त बनाई थी।
 - ▲ 2005 से, यूरोप, कनाडा और अमेरिका में 100 किलोमीटर से अधिक मुक्त-अंतरिक्ष QKD के प्रयोग किए जा चुके हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत को QKD-उलझाव संचार के क्षेत्र में अभी लंबा रास्ता तय करना है।

चुनौतियाँ

- इस तकनीक के विकास के लिए केवल पर्याप्त धन ही नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समर्पित बहु-विषयी टीम भी आवश्यक है।
- मुक्त-अंतरिक्ष में वायुमंडलीय कमियाँ त्रुटियों को बढ़ाती हैं।
- भारत ने 2020 के दशक में इस दिशा में देरी से शुरुआत की है और उसे वैश्विक नेताओं की बराबरी करनी है।
- ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग से स्थिर संचार चैनल मिलते हैं, जबकि मुक्त-अंतरिक्ष में यह स्थिरता नहीं होती।

भविष्य की योजनाएँ

- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के अंतर्गत भारत उपग्रह-आधारित लंबी दूरी की QKD पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- इसमें क्वांटम स्टार्टअप्स, स्वदेशी उपकरणों और प्रयोगशाला से बाज़ार तक तकनीकों को समर्थन दिया जा रहा है।
- भारत का लक्ष्य आगामी 5-10 वर्षों में उपग्रह-आधारित QKD और पूरे देश में एक क्वांटम नेटवर्क स्थापित करना है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

- उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था।
- वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे — देशभक्त, शिक्षाविद, सांसद, राजनेता और मानवतावादी।
- उन्होंने अपने पिता सर अशुतोष मुखर्जी से विद्रूता और राष्ट्रवाद की विरासत पाई, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कुलपति और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

मुख्य योगदान

- उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने, जहाँ उन्होंने भारतीय भाषाओं और शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- वे प्रारंभ में कांग्रेस से जुड़े और बाद में हिंदू महासभा में शामिल हो गए, जहाँ वे कार्यकारी अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया।

- बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में, उन्होंने औपनिवेशिक हस्तक्षेप का विरोध किया और अकाल राहत प्रयासों में योगदान दिया।
- स्वतंत्रता के पश्चात्, उन्होंने उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया और प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की स्थापना में सहायता की, इसके पश्चात् 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की।
- उन्हें “संसद का शेर” के रूप में जाना जाता था — वे एक प्रभावशाली वक्ता थे, जो राष्ट्रीय एकता विशेषकर जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के पक्षधर थे।

विरासत

- उनका निधन 1953 में कश्मीर में हिरासत के दौरान हुआ और वे आज भी अपने देशभक्ति, नेतृत्व और भारत की एकता के प्रति समर्पण के लिए स्मरण किए जाते हैं।

Source :PIB

उमीद पोर्टल

संदर्भ

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है ताकि UMEED पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके, जिससे सभी वक्फ संपत्तियाँ छह महीने के अंदर अपलोड की जा सकें।

UMEED पोर्टल के बारे में

- यह पोर्टल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भारतभर में वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु विकसित किया गया है।
- UMEED सेंट्रल पोर्टल — जिसका पूर्ण रूप “यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995” है — एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जो वक्फ संपत्तियों की रीयल-टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी को सक्षम बनाता है।

पोर्टल की प्रमुख विशेषताएँ:

- सभी वक्फ संपत्तियों की भू-टैगिंग के साथ डिजिटल सूची का निर्माण

- ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली जो अधिक उत्तरदायी सेवा सुनिश्चित करती है
- पारदर्शी लीज़ और उपयोग ट्रैकिंग
- GIS मैपिंग और अन्य ई-गवर्नेंस उपकरणों के साथ एकीकरण
- सत्यापित रिकॉर्ड और रिपोर्ट तक जनसाधारण की पहुँच

Source: PIB

ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमला

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के तीन प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों — नतांज, फोर्डो और इस्फहान — पर हमला किया है।

पृष्ठभूमि

- इन हमलों को ऑपरेशन “मिडनाइट हैमर” कहा जा रहा है, जो इजराइल के साथ युद्ध के बीच ईरान के परमाणु ढांचे को निशाना बनाने वाली अमेरिका की प्रथम सीधी सैन्य कार्रवाई है। यह अभियान इजरायली बलों के साथ समन्वय में संचालित किया गया।

US has Bombed Nuclear Sites in Iran



 Fordow: Underground uranium enrichment facility. Iran's most heavily fortified site, buried under a mountain near Qom

 Natanz: Main uranium enrichment facility. Large underground complex housing advanced centrifuges

 Isfahan: Uranium conversion facility. Processes yellowcake into uranium hexafluoride (UF6) gas for enrichment at other sites.

अन्य परमाणु स्थल (जिन्हें निशाना नहीं बनाया गया)

- बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र: वाणिज्यिक संयंत्र है, रूसी ईंधन से संचालित और IAEA निगरानी के अधीन।
- आराक हैवी वॉटर रिएक्टर: प्लूटोनियम उत्पादन की संभावना वाला स्थल; JCPOA के तहत पुनः विन्यस्त।
- तेहरान अनुसंधान रिएक्टर: अल्प-संवर्धित यूरेनियम उपयोग के लिए पुनः डिज़ाइन किया गया।

सांयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)

- JCPOA, जिसे सामान्यतः “ईरान परमाणु समझौता” कहा जाता है, एक ऐतिहासिक कूटनीतिक समझौता है जो 2015 में ईरान और P5+1 देशों — संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी — तथा यूरोपीय संघ के बीच हुआ था।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण बना रहे और ईरान परमाणु हथियार न विकसित करे, इसके बदले उसे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी गई।
- हालांकि, 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका इस समझौते से एकतरफा रूप से बाहर निकल गया।

JCPOA के मुख्य प्रावधान

- यूरेनियम संवर्धन की सीमा: ईरान ने यूरेनियम को अधिकतम 3.67% शुद्धता तक ही संवर्धित करने की सहमति दी (जो परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक 90% से काफी कम है)।
 - वह केवल 300 किलोग्राम अल्प-संवर्धित यूरेनियम रख सकता था, जो पहले 10,000 किलोग्राम से अधिक था।
- सेंट्रीफ्यूज में कमी: ईरान ने सेंट्रीफ्यूज की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी, जिनमें से केवल 5,060 को संवर्धन के लिए उपयोग किया जा सकता था।
- फोर्डों: 15 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं थी।

- नतांजः** केवल यही स्थल था जहाँ सख्त निगरानी के तहत यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दी गई।
- आराक में हैवी वॉटर रिएक्टर:** ईरान को इस रिएक्टर को पुनः डिज़ाइन और पुनर्निर्मित करना था ताकि प्लूटोनियम का उत्पादन रोका जा सके।
 - ईरान ने IAEA निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों — घोषित और अघोषित दोनों — तक नियमित और दीर्घकालिक पहुँच की अनुमति देने पर सहमति दी।
- प्रतिबंधों से राहत:** इसके बदले, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए परमाणु-संबंधित प्रतिबंध हटाए गए, जिससे ईरान को वैश्विक बाज़ारों और जमे हुए धन तक पहुँच मिली।

Source: IT

ईरान ने होर्मुज जलडमरुमध्य को अवरुद्ध करने का कदम उठाया

समाचार में

- ईरान की संसद ने ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका के हमलों के चलते होर्मुज जलडमरुमध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे ईरान-इजराइल संघर्ष और तीव्र हो गया है।

होर्मुज जलडमरुमध्य के बारे में

- होर्मुज जलडमरुमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- यह ओमान और ईरान के बीच स्थित है।



- यह फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक पहुँचने का एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है और इसे विश्व के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकरे समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है।
- यह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और कुवैत जैसे खाड़ी देशों के लिए प्राथमिक निर्यात मार्ग है।
- यह प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल (विश्व आपूर्ति का लगभग पाँचवाँ हिस्सा) और बड़ी मात्रा में एलएनजी परिवहन करता है।
 - वर्ष 2024–25 में यह वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का एक-चौथाई से अधिक हिस्सा संभालता रहा, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है।

बंद होने के प्रभाव

- सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पास होमुज जलडमरुमध्य के विकल्प के रूप में सीमित स्थल-आधारित पाइपलाइन हैं, जो इसकी कुल क्षमता का आधे से भी कम कवर करती हैं।
- जलडमरुमध्य का कोई भी बंद होना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करेगा और शिपिंग तथा बीमा लागतों में वृद्धि करेगा।
- भारत अपनी 90% कच्चे तेल की आवश्यकता का आयात करता है, जिसमें लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन होमुज जलडमरुमध्य से होकर आता है।
 - हालाँकि, भारत के पास विविधीकृत तेल स्रोत हैं, और अब रूसी कच्चा तेल कुल आयात का 38% हिस्सा बनाता है।
- यदि संकट लंबा चलता है, तो इससे भारत की आर्थिक वृद्धि कमज़ोर हो सकती है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, रुपये पर दबाव आ सकता है और राजकोषीय स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है।

Source: BS

सरिस्का बाघ अभ्यारण्य

संदर्भ

- सरिस्का टाइगर रिजर्व की 'क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट' (CTH) की सीमा को तार्किक रूप से पुनर्निर्धारित करने की एक योजना बनाई गई है, जिससे वे 50 से अधिक मार्बल और डोलोमाइट खदानें फिर से चालू हो सकती हैं जिन्हें एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था।
 - यदि यह योजना स्वीकृत होती है, तो नई सीमाओं से क्षतिग्रस्त बाहरी क्षेत्रों को बाहर कर दिया जाएगा, जिससे खनन गतिविधियाँ प्रतिबंधित एक किलोमीटर क्षेत्र से बाहर आ जाएँगी।

परिचय

- सरिस्का टाइगर रिजर्व या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है।
 - यह पार्क राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है।
- सरिस्का टाइगर रिजर्व कभी अलवर रियासत का शिकार क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात्, सरिस्का वन को 1955 में प्रथम बार बन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया।
 - 1978: भारत सरकार द्वारा इसे 11वाँ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
 - 1982: सरिस्का बन्यजीव अभ्यारण्य को सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया।

Source: IE

GBU-57 विशाल आयुध भेदक/MOP

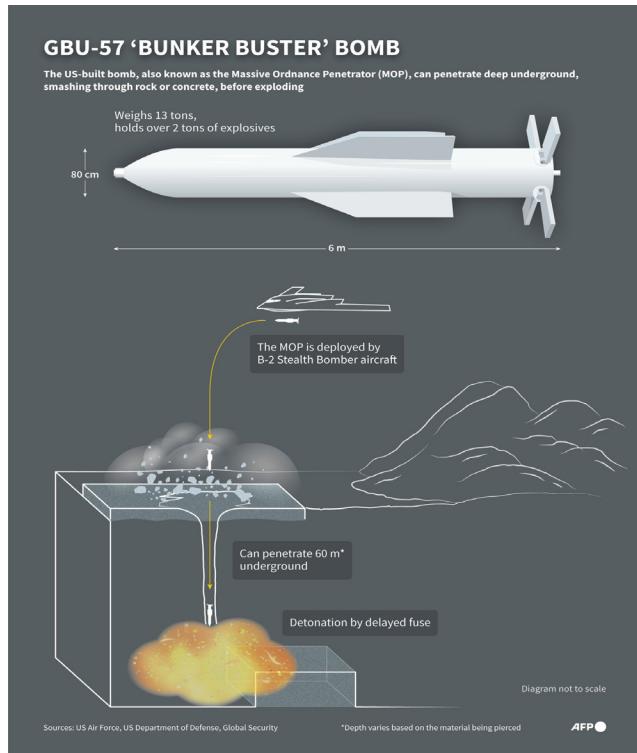
संदर्भ

- अमेरिकी सेना ने ईरान के तीन स्थलों पर हवाई हमले किए हैं, जो इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी को दर्शाते हैं।
 - फोर्डो, जो एक पहाड़ के नीचे 300 फीट की गहराई में स्थित है, वह स्थल है जहाँ ईरान ने कथित तौर

पर हथियार-उपयोगी यूरोनियम संवर्धन और उसका भंडारण करने का प्रयास किया।

परिचय

- GBU-57 मैसिव ऑर्डरेंस पेनिट्रेटर (MOP) अमेरिका के सैन्य भंडार में सबसे बड़ा गैर-परमाणु बम है।
- यह बोइंग द्वारा निर्मित और GPS द्वारा मार्गदर्शित है, और विशेष रूप से गहराई से दबे और मजबूत बंकरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।



- MOP की लंबाई 20.5 फीट और व्यास 31.5 इंच है, तथा इसका वजन लगभग 30,000 पाउंड है — जिसमें 5,300 पाउंड उच्च-विस्फोटक सामग्री शामिल है।
- यह बम सुदृढ़ कंक्रीट की 200 फीट से अधिक गहराई में प्रवेश कर सकता है और फिर विस्फोट करता है।
- इसका आवरण उच्च-प्रदर्शन वाले इस्पात मिश्रधातु से बना है, जो प्रवेश के समय अत्यधिक टक्कर बलों को सहने में सक्षम बनाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश फोर्डों जैसी गहराई तक पहुँचने में सक्षम कोई गैर-परमाणु हथियार प्रणाली नहीं रखता।

Source: IE

INS नीलगिरि: प्रथम प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट

संदर्भ

- INS नीलगिरि विशाखापत्तनम बंदरगाह पर पहुँचा है ताकि वह ईस्टर्न नेवल कमांड के 'सनराइज़ फ्लीट' में शामिल हो सके।

क्या आप जानते हैं?

- इस वर्ग के अन्य छह जहाज — हिमगिरी, तरागिरी, उदयगिरी, दुनागिरी और विंध्यगिरी — एमडीएल (मुंबई) और जीआरएसई (कोलकाता) में विभिन्न निर्माण चरणों में हैं।

INS नीलगिरि

- यह मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता द्वारा शिवालिक क्लास के अनुसरण के रूप में निर्मित किया गया है।
 - ▲ यह प्रोजेक्ट 17ए का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट है।
 - प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स, प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक क्लास) फ्रिगेट्स की उन्नत श्रेणी हैं, जिनमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर तथा आधुनिक प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियां शामिल हैं।
- यह ब्लू-वॉटर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है और वायु, सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं से सुसज्जित है।
- ये बहुउद्देशीय युद्धपोत गहरे समुद्र में संचालित होते हैं और पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम हैं।

Source :IE

INS तमाल

संदर्भ

- भारतीय नौसेना अपने नवीनतम स्टील्थ मल्टी-रोल युद्धपोत INS तमाल को रूस के कालिनिनग्राद में कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

परिचय

- यह भारतीय नौसेना का अंतिम ऐसा युद्धपोत होगा जिसे भारत के बाहर निर्मित किया गया है, और यह विगत दो दशकों में रूस से शामिल किए गए क्रिवाक श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला में आठवाँ है।
- INS तमाल, तुषिल श्रेणी का दूसरा जहाज है, जो इसके पूर्ववर्ती तलवार और तेग श्रेणी के उन्नत संस्करण हैं।
- इस श्रृंखला के पूरे होने के बाद, भारतीय नौसेना चार विभिन्न श्रेणियों में ऐसी 10 युद्धपोतों का संचालन करेगी, जिनमें समान क्षमताएँ होंगी।

INS तमाल

- इस जहाज में 26% स्वदेशी घटक शामिल हैं, जिनमें समुद्र और जमीन दोनों लक्ष्यों को भेदने वाली लंबी दूरी की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल शामिल है।
- इस पोत के शस्त्रास्त्र प्रणाली में इसके पूर्ववर्तियों की तुलना में महत्वपूर्ण उन्नयन किए गए हैं।
- पोत की नई डिज़ाइन में बेहतर स्टीलथ विशेषताएँ और अधिक स्थिरता क्षमताएँ शामिल हैं, जो इसे बहुआयामी अभियानों के लिए उपयुक्त बनाती हैं।

Source: TH

